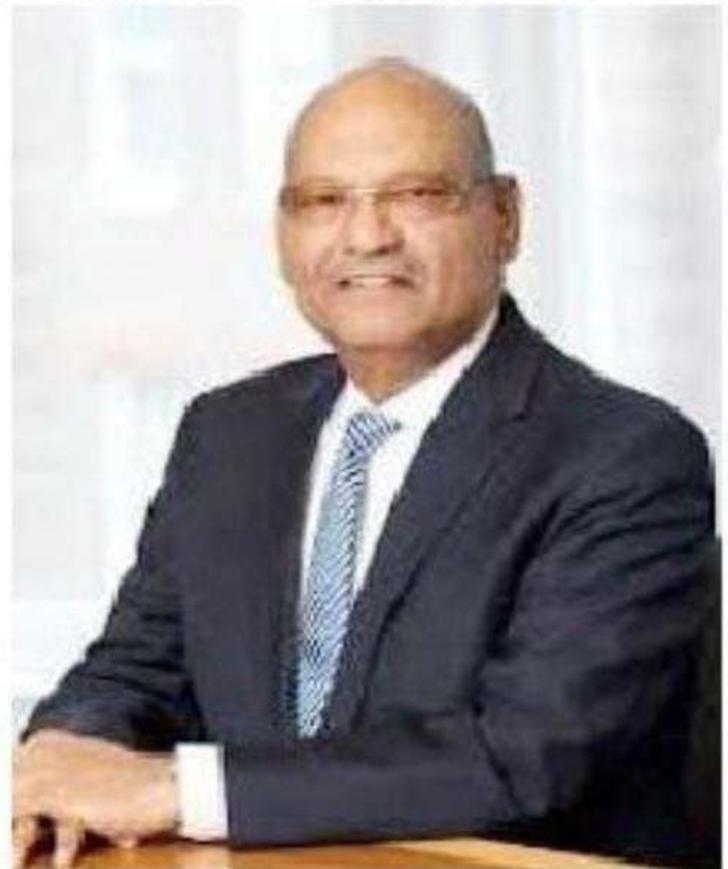


पश्चिम एशिया संघर्ष ने भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के प्रयासों की अत्यावश्यकता को फिर उजागर किया

भास्कर समाचार सेवा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने आयातित हाइड्रोकार्बनों पर भारत की गहरी निर्भरता को लेकर चिंतों को फिर से बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक सप्लाई बाधा के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक जोखिम उजागर हो रहे हैं। यह चुनौती स्ट्रक्चरल है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था वैश्विक सप्लाई झटकों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। तेल और गैस मिलकर भारत के वार्षिक आयात बिल का लगभग 176 अरब डॉलर हिस्सा बनाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक अस्थिरताओं के प्रति अधिक



प्रभावित रहती है। उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि ताजा संकट इस बात की याद दिलाता है कि ऊर्जा सुरक्षा का आर्थिक स्थिरता से गहरा संबंध है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सरकार से इस क्षेत्र को तुरंत राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करने का आग्रह किया है।